>

Title: Discussion regarding Internal Security.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज आंतरिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा हो रही है। पिछले तीन दिनों से सभी टी.वी. चैनल्स और प्रिंट मीडिया में यह समाचार प्रमुखता से दिया जा रहा है कि आईबी ने दिल्ली पुलिस और सरकार को सतर्क किया है कि दिल्ली में किसी भी समय भीषण आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं। दो सप्ताह या छः दिसम्बर के आसपास कोई ऐसी आतंकवादी घटना होगी। दिल्ली की एक करोड़ 60 लाख जनता किस तरह आतंक के साए में जी रही है। अभी कुछ दिन पूर्व गृह मंत्री जी ने पुलिस महानिदेशकों के वार्षिक सम्मेलन की बैठक में कहा था कि हमारे परमाणु संयंत्र, पावर इंस्टालेशंस, डिफेंस एस्टीब्लिशमेंट्स और हमारे अन्य जितने भी इस प्रकार के एस्टीब्लिशमेंट्स हैं, वे सब खतरे में हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि थल, जल और वायु से आतंकवादी घटना और हमला हो सकता है।[rep27]

[r28] उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सुरक्षा सलाहकार लगातार पिछले दो वर्षों से बार-बार लगातार इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे चार महानगर खतरे में हैं। वे बार-बार कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रमुख स्थानों को बहुत खतरा है। कल श्री पी. चिदम्बरम जी ने राज्य सभा में इस बात को स्वीकार किया है कि आतंकवादियों का बहुत सारा धन हमारे देश के स्टॉक एक्सचेंजेज में लग रहा है और आतंकवादी हमारे देश के स्टॉक एक्सचेंजेज को पूरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। इन सारी चेतावनियों का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है और आतंकवादी घटनाएं लगातार घटती जा रही हैं। लोग आतंकवाद के साये में जी रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों को कोई आतंक प्रभावित नहीं करता है। आतंकवादी बिलकुल आतंकित नहीं होते, बल्कि जनता का जीना मुहाल हो रहा है। इसके कारण लोगों का विश्वास इस सरकार से उठ गया है, क्योंकि सारी चेतावनियों के बाद भी सरकार आतंकवादियों का मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसलिए सरकार हमेशा घबराहट में रहती है कि कब कोई आतंकवादी घटना कहां घट जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दो वर्षों की आतंकवादी घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं। दिनांक 23 नवम्बर, 2007 को लखनऊ, वाराणसी और फैजाबाद में कचहरी परिसर में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई और 59 से अधिक घायल हुए। चेतावनी के बाद यह सब हुआ। वहां चेतावनी दी गई थी कि सदन के एक प्रमुख व्यक्ति श्री राहुल गांधी जी का अपहरण हो सकता है और आतंकवादी इस प्रकार का प्लान बना रहे हैं। चेतावनी दी गई थी कि दिल्ली में तिहाड़ जेल को तोड़ा जाएगा और आतंकवादियों को छुड़ाकर ले जाएंगे, परन्तु इसके बाद भी यह घटना यू.पी. में हुई। 14 अक्तूबर, 2007 को लुधियाना के सिनेमाघर में ब्लास्ट हुआ जिसमें 6 मरे और 25 घायल हुए। 25 अगस्त, 2007 को हैदराबाद में सीरियल ब्लास्ट्स हुए जिनमें 42 लोग मरे और 54 घायल हुए। 18 मई, 2007 को मक्का मस्जिद, हैदराबाद में ब्लास्ट हुआ, 14 मरे और 100 घायल हुए। 19 फरवरी, 2007 समझौता एक्सप्रैस में पानीपत के निकट ब्लास्ट हुआ, जिसमें 68 मरे, 125 घायल हुए। 11 जुलाई 2006 मुम्बई की रेलों में बम ब्लास्ट हुए जिनमें 187 मरे और 700 घायल हुए। 8 सितम्बर, 2006 को मालेगांव में विस्फोट हुआ, जिसमें 27 मरे। 7 मार्च, 2006 को वाराणसी के संकट मोचन हनुमान मंदिर में विस्फोट हुआ 16 मरे और 100 घायल हुए। दिनांक 29 अक्तूबर, 2005 को दिल्ली, ...(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI): Sir, I may be permitted to intervene for a minute.

Sir, I, on behalf of the Government, made a request in the presence of you, Sir, sitting in the Chair and the entire House agreed, that today two important Bills have to be cleared. One Bill has to go to Rajya Sabha tomorrow. In-between I was in Rajya Sabha. In the meanwhile, for any reason, it is obvious that the House was adjourned till 2.30 p.m.

Let him speak, but if the passage of this Bill is not ensured today, how can I take it to Rajya Sabha tomorrow? The Government business cannot be a casualty, always like this. I have never seen it at any time. ...(*Interruptions*)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : It was for you to bring it in time. ...(*Interruptions*) It is written here ...(*Interruptions*) इसमें लिखा हुआ है कि इस पर डिबेट 2.30 बजे शुरू होगी।

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: No, it is not my fault. I did not hide it. I said it कि इसके बाद कोई बिजनैस होगा। हाउस के अंदर बोला। सरकार की तरफ से बोला। उस समय आप भी प्रजैंट थे। ...(व्यवधान) इसके बाद मैं राज्य सभा चला गया। पता चला कि आपने इस विषय पर बहस शुरू कर दी। अगर आप लोग कोआपरेट नहीं करेंगे, तो कैसे काम चलेगा, मैं इसे यहां से पास कराने के बाद राज्य सभा में कब ले जाऊंगा? ...(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : आप इसे अभी तो चलने दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: नहीं, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं। मेरा सुझाव है कि मल्होत्रा जी, पूरा बोलें, हम उन्हें नहीं रोकेंगे। इस बहस को आप चलाइए, लेकिन कोई किसी वक्त बीच में इस बहस को रोक कर आप इन दो बिलों को क्लीयर कर दीजिए, बस मैं यही चाहता हूं।

श्री मोहन सिंह : छः बजे के बाद बहस चलाईए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: छः बजे कोई सदस्य उठकर कहेगा कि कोरम नहीं है, तो फिर ये बिल कैसे पास होंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : कोरम बनाए रखना तो आपकी जिम्मेदारी है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I asked it from the hon. Members of the House.

...(*Interruptions*)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI: I am not objecting. मैं मल्होत्रा जी को बीच में नहीं रोकना चाहता हूं। वे अपनी बात बोलें, लेकिन मेरा यही

निवेदन है कि इन दोनों बिलों को आज क्लीयर कर दिया जाए, ताकि ये कल राज्य सभा में जा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा करते हैं कि इसे 4.00 बजे तक चलाते हैं। उसके बाद लैजिस्लेटिव बिजनैस को चलाएंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, 4.00 बजे के बाद, कल फिर से कंटीन्यू कीजिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: That will continue.[s29][r30]

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): You continue. We have already taken up the topic....(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आपके हुक्म से मैं कंटीन्यू कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि सात मार्च, 2006 को वाराणसी में संकटमोचन मंदिर में विस्फोट हुआ, 16 लोग मरे, 100 घायल हुए। 10 अक्टूबर, 2005 को दिल्ली में 57 लोग मरे, 153 घायल हुए। मैंने दो साल की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया है, परन्तु इन घटनाओं के बारे में सबसे जो चिन्ताजनक बात है, कष्टदायक बात है और जो बहुत ही शॉकिंग है कि इन सारी घटनाओं में एक भी आतंकवादी मारा नहीं गया। कोई आतंकवादी पकड़ा गया हो या उस पर मुकदमा चल रहा हो, ऐसी भी कोई सूचना नहीं है। जितनी भी बाद की घटनाएं हुई, उसके अगले दिन बड़े-बड़े अक्षरों में बड़े-बड़े बयान दिये गये कि इनका सुराग लगा लिया गया है, लोग पकड़े गये हैं और मामला सुलझ रहा है। लेकिन एक भी आतंकवादी दो सालों का जो मैंने बताया है, उनमें से एक भी घटना नहीं सुलझी है, एक भी घटना में कोई मुकदमा नहीं चलाया गया और जो आतंकवादी आये थे, वे मारे नहीं गये। यह स्थिति नहीं हुई, मैंने देखा है, कांग्रेस की अध्यक्षा गुजरात में गई थीं और उन्होंने गुजरात में जाकर इस बात का उल्लेख किया कि जब एन.डी.ए. की गवर्नमेंट थी, तब भी घटनाएं होती थीं और चाहे घटना रघुनाथ मंदिर की हो, अक्षरधाम की हो या संसद पर हो, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया और कहा कि ये घटनाएं उस समय क्या नहीं होती थीं। इसका सवाल नहीं है कि घटनाएं उस समय नहीं होती थीं, मैं मानता हूं कि ये घटनाएं हुई थीं, परन्तु उन घटनाओं के अन्दर तीनों चारों घटनाओं का जो उन्होंने उल्लेख किया, इसमें जितने आतंकवादी आये थे, सारे आतंकवादी जब मारे गये, बाद में उनमें से पकड़े गये, गिरफ्तार हुए, पोटा के अन्दर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उनमें से बहुतों को सजाएं हुई और सजाएं देने का काम हुआ। परन्तु इन घटनाओं के अन्दर दो वर्षों के अन्दर इस प्रकार की घटना नहीं हुई, जिसके अन्दर आतंकवादी वहीं मार दिये गये हों। इनमें से एक भी घटना का सुराग तक नहीं मिला है, जितनी घटनाओं का मैंने उल्लेख किया।

शुरू में तो बहुत ज्यादा इस बात का दावा किया गया कि सुराग मिल गये हैं, यहां से कराची में कॉल हुई थी, यहां से बंगलादेश में लोग चले गये, इन्दौर से आये थे, परन्तु अब उसके बाद सारे के सारे मामले ठंडे बस्ते में पड़े हैं। इंटेलीजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरैक्टर का यह कहना है कि कोई आतंकवादी जब भारत में घुसपैठ करता है तो उसके मन में कोई भय या दहशत नहीं होती। उसे लगता है कि जैसे वह कहीं सैर-सपाटे के लिए या है। भारत में उसे छिपने या शरण पाने के अनेक स्थान मिल जाते हैं। यहां सुरक्षा तंत्र अत्यन्त ढीला-ढाला है और सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिए कृतसंकल्प नहीं है। आतंकवादियों के मन में यह विश्वास रहता है कि घटना करने के बाद वह आसानी से कहीं लुप्त हो जायेगा या अपने देश पाकिस्तान या बंगलादेश में आसानी से वापस लौट जाएगा। अगर वह पकड़ा भी गया तो आसानी से उसकी जमानत हो जायेगी, क्योंकि अब पोटा नहीं है। इसलिए अब जमानत होना बहुत आसान है। पुलिस के विरूद्ध आसानी से यह आरोप लगाया जा सकेगा कि वह एक विशेष समुदाय के लोगों का उत्पीड़न कर रही है। यदि मुकदमा चलने की नौबत आती है तो ज्यादा संभावना यह रहेगी कि वह छूट जायेगा और अगर उसे सजा भी हो गई तो मानवाधिकार का मुखौटा पहने बहुत से ऐसे लोग होंगे, जो उसे बचाने के लिए सामने आएंगे। कुल मिलाकर खतरा कम और बचने की संभावनाएं ज्यादा हैं। ऐसे वातावरण में आतंकवादियों को भारत में आने में क्या दिक्कत है। वे किसी भी रास्ते से भारत में प्रवेश कर सकते हैं।

अध्यक्ष जी, अमेरिका में 11 सितम्बर की आतंकवादी घटना हुई। उस घटना के बाद अमेरिका में आज तक कोई दूसरी घटना नहीं हुआ, सात साल बीत गये हैं। उनके यहां घटना क्यों नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका ने उसे अमेरिका के खिलाफ एक आक्रमण समझों और उसकी लड़ाई, जैसे हमले की लड़ाई करते हैं, युद्ध की लड़ाई करते हैं, युद्ध स्तर पर उन्होंने उसका मुकाबला किया। उसने अपने कानूनों को बहुत कठोर बनाया और उनमें इंटेलीजेंस एजेंसियां वहां पर इतनी मजबूत हुई कि कोई घटना इन सात वर्षों में सुनने को नहीं आई। स्पेन और इंग्लैंड ने भी इसी प्रकार से अपने आतंकवादी कानूनों को मजबूत किया और आतंकवादियों को पकड़कर सजाएं भी दीं, परन्तु अजीब बात है कि यहां पर हमारा देश, जो सबसे ज्यादा आतंकवादी से ग्रस्त देश है, यहां पर 90 हजार लोग अब तक आतंकवादी के शिकार हो चुके हैं, जबकि हमारे चार युद्ध हुए। उन चारों युद्धों में जब लड़ाई हुई तो उन चारों युद्धों में 8023 लोग मारे गये।[R31] परंतु आतंकवादियों के हाथों मरने वालों की संख्या 90 हजार से ज्यादा है। इतने ज्यादा लोग मारे जाएं, लेकिन इसके लिए क्या हुआ? हमने उनका मुकाबला करने के लिए क्या किया? एकमात्र कानून पोटा था, उस अकेले कानून, जिसके माध्यम से आतंकवाद से मुकाबला हो सकता है, हमने मुकाबला करने के बजाए उस पोटा कानून को ही खत्म कर दिया। यूनाइटेड नेशंस ने सारी दुनिया को यह लिखा है कि 1373 रेजोल्यूशन के अंतर्गत अपने-अपने यहां कोई कानून बनाइए, जो आतंकवाद से लड़ सके, जो वित्तीय सहायता उनको मिलती है, उसका मुकाबला हो सके। परंतु हमारा अकेला एक बदकिस्मत देश है कि हमारे यहां जो कानून पहले था, उसे भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, हमारे यहां जो कानून हैं, वे बहुत पुराने हैं, जो उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सरकार ने अपनी वोट बैंक की राजनीति के कारण, वोट लेने के लिए खास तौर पर पोटा जैसे कानून को खत्म करके इस देश के हितों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। उन्होंने इस देश को आतंकवादियों के हाथों जब चाहे, जिस जगह चाहे, जिस तरह से चाहे...(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह : पोटा में कहां वोट बैंक है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : पोटा में वोट बैंक है। आतंकवादियों को बताने के लिए ...(व्यवधान) मुसलमानों को बताने के लिए ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Those hon. Members who speak without my permission, should not be recorded. Only the speech of Prof. Malhotra should be recorded.

*(Interruptions) â€¦**

* Not recorded

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is going on record.

*(Interruptions) â€¡ **

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : इस देश के साथ विश्वासघात किया गया है, इसके लिए आने वाली पीढ़ियां कभी क्षमा नहीं करेंगी,...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not waste the time of the House. Please sit down.

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is going on record.

*(Interruptions) â€¡**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is going on record except what Prof. Malhotra says.

*(Interruptions) â€¡**

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आतंकवाद का मुकाबला करने की तैयारी में यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट तैयार की। हिंदुस्तान टाइम्स में 11 सितम्बर को उसके अंश प्रकाशित हुए। रिपोर्ट में बताया कि जुलाई के महीने में उन्होंने सरकार को यह रिपोर्ट दी थी। हिंदुस्तान टाइम्स के इस रिपोर्ट के मुताबिक:

> "A confidential United Nations report has punched huge holes in India's anti-terrorism preparedness, after its first ever scrutiny of everything from national laws to border check posts to judiciary to banks to police work and passports.
> The draft report of the Counter Terrorism Committee of the UN Security Council, seen by HT, is a stinging indictment of how the country's counter-terrorism structures are in disarray. The report was given to the Indian Government in July.
> Terrorism in India, according to some estimates, has claimed 70,000 lives over the years.
> Many of the problems faced by India's current counter-terrorism regime could be tackled if India were to adopt comprehensive counter-terrorism legislation, the report said. Some of India's counter-terrorism legislation dates back to Independence, and the primary terrorism-related law, the Unlawful Activities (Prevention) Act was passed in 1967 with successive amendments. Two anti-terrorism laws, known as TADA and POTA by their

---

> * Not recorded
> acronyms, have been scrapped. Under the Prevention of Money Laundering Act, India set up a Financial Intelligence Unit in March 2006.
> It is a cause of concern that Indian law enforcement structures lack a national counter-terrorism database which would enable them to remain informed on a real time basis, of terrorist related events that occur from the country."

इस रिपोर्ट में जितना इंडिक्टमेंट हुआ है, जितना इस सरकार की कमजोरियों को उजागर किया गया, मैं सारी रिपोर्ट आपके सामने नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन यह रिपोर्ट सिद्ध करती है कि यह सरकार टेररिज्म से लड़ने के योग्य भी नहीं है, इसकी नीयत नहीं है, इसकी विल नहीं है और जो मैंने कहा था, जिसके ऊपर आपत्ति की गयी कि केवल वोटों के लिए, वहां पर एक मैसेज देने के लिए इसे किया। ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not disturb.

(Interruptions)[p32]

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. Next speaker is from your Party. He could reply.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : हमारी आंतरिक सुरक्षा को जो प्रमुख खतरे हैं, उनमें से एक यह है कि सारे देश में आईएसआई द्वारा बम ब्लास्ट किए जा रहे हैं या दूसरी संस्थाएं कर रही हैं। इनके अलावा हमारे सामने इस प्रकार के खतरे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार की स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत वहां जो आतंकवाद किया जा रहा है, जिसे वे इस्लामिक आतंकवाद का नाम देते हैं, वह जम्मू कश्मीर में चल रहा है। देश के अन्य भागों में आईएसआई द्वारा प्रायोजित लश्कर-ए-तैयबा, जैशे मोहम्मद, हूजी संगठन द्वारा बम धमाके व अन्य प्रकार से आतंकवाद, माओवादी व नक्सली ग्रुपों द्वारा देश के बहुत बड़े भाग में हिंसात्मक कार्यवाही, खास तौर से हमारी सीमाओं पर मदरसों का बढ़ता भीषण जाल और उससे निकलने वाले जेहादी मानसिकता के छात्र, पाकिस्तान आईएसआई अल कायदा व विदेशी जहाजी ग्रुपों द्वारा आतंकवादियों को मिलने वाला अपार धन और शस्त्र, बंगलादेश से होने वाली भारी घुसपैठ और उनके द्वारा कानून व्यवस्था।

जम्मू कश्मीर में इस समय जो स्थिति है, कहा जा रहा है कि वहां स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Lal Singhji, when you will be on your legs, how will it possible for me to control them?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मेरे पास वे सारी कटिंग्स हैं। अगर मैं पढ़ना शुरू करूं कि 16-16 साल के बच्चों को कैसे रेत-रेतकर मारा जा रहा है, कैसे उनकी आंखें निकाली जाती हैं, कैसे उनके दिल निकाले जाते हैं, कैसे जिगर काट दिए जाते हैं, कैसे उन्हें इन्फार्मर मानकर उनकी हत्या की जाती है, सारे परिवार नष्ट हो जाते हैं और यह कह रहे हैं कि बहुत सुधार हो रहा है।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded except the speech of Shri Malhotra.

*(Interruptions) â€¦**

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : कांग्रेस अध्यक्षा को गुजरात के दंगे ध्यान में आये, लेकिन दिल्ली में मारे गए सिखों का ध्यान नहीं आया, कश्मीर के पांच लाख पंडित बाहर निकले हुए हैं, उनके बारे में ध्यान नहीं आया। वहां सत्तर हजार लोग मारे गए, उनके बारे में कोई शब्द नहीं कहा।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded except the speech of Shri Malhotra.

*(Interruptions) â€¦ **

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति खराब होने के कारण थोड़ा अंतर जरूर दिखता है, परन्तु पाकिस्तान में आतंकवाद के अड्डे कायम हैं, यह प्रणब मुखर्जी साहब भी कह चुके हैं, गृह मंत्री जी भी कह चुके हैं और एंटोनी साहब भी कह चुके हैं। हर आदमी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डे कायम हैं, इसलिए हमें खबरदार रहने की जरूरत है।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. Nothing is going on record.

*(Interruptions) â€¦ **

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : बार्डर से हमारी सेनाओं पर बहुत हमले हुए और यह कहा गया कि हमले हुए हैं, परन्तु कहा गया कि हमले पाकिस्तानी सेना ने नहीं किए, जो घुसपैठ करके आने वाले थे, उन्होंने वहां से गोलियां चलाई। बीसियों की तादाद में घटनाएं हुई, परन्तु यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने वहां फायरिंग नहीं की। हमारे जवान मारे गए हैं। वहां इसी प्रकार से घटनाएं चल रही हैं। इसलिए बहुत खबरदार होने की जरूरत है, यह न समझा जाए कि वहां जैसे ही उनके हालात सुधरेंगे, फिर से ये घटनाएं बढ़ने लग जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडितों का जो मामला है, जो बार-बार हमारे सामने आता है, जो आतंकवाद का शिकार हुए हैं और उसी कारण जो आज

---

* Not recorded

दुर्दशा में पड़े हुए हैं, उनके रहने या कश्मीर में लौटने का कोई मापदंड आज तक नहीं बनाया गया।[N33]

उनके बारे में भी विचार करने की जरूरत है। एक मामला मैंने कहा था, उसका उल्लेख ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded.

*(Interruptions) â€¦ **

उपाध्यक्ष महोदय : गोयल जी, आपकी पार्टी के मैम्बर जब बोलेंगे तब वे इन सब बातों का जवाब देंगे।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आज इनको आप बोलने का टाइम मिलना चाहिए। पार्टी के व्हिप साहब कह दें कि आज यही बोलेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब भी बैठ जाइये।

â€¦(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, अभी तो मैंने कुछ पूछा नहीं है। ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. Do not waste the time of the House. Shri Lal Singh, please sit down.

...(*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : लाल सिंह जी, आप बैठ जाइये।

â€¦(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, ये लोग बीच में इधर-उधर का जिक्र करते हैं। ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, there should be no disturbance.

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please keep silent, Shri Goyal.

...(*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अगर मुझे कहना ही है, तो मैं कहूंगा कि कितनी और लाशें चाहिएं, कितने लोग और मरने चाहिए जब तक आप पोटा कानून बनायें। ...(व्यवधान)

* Not recorded

उपाध्यक्ष महोदय : हान्डिक जी, आप अपने मैम्बर्स से कहिये कि चार बजे बिल पास करना है।

â€¦(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैंने यह कही कि जम्मू कश्मीर के बाद यहां पर नक्सलवाद की समस्या है। देश में कुल 604 जिले हैं जिनमें से 160 से लेकर 180 जिलों पर एक तरह से उनका कब्जा है। उनके हाथ में न्याय तंत्र है। वह कर वसूलते हैं, जमीनें बांटते हैं, सरकारी भूमि बांटते हैं और भीषण हिंसा में लिप्त रहते हैं। वे निर्दोष लोगों और पुलिस बलों की भी हत्या करते हैं। यहां तक स्थिति पहुंच गयी है कि माओवाद जिसके साथ सीपीआई, सीपीएम का बहुत निकट के संबंध रहे हैं, उनको कहना पड़ रहा है कि नंदीग्राम में जो घटनाएं हुई, वे माओवाद के कारण हुई, नक्सलवाद के कारण हुई। पहले तो उनके साथ पींगें बढ़ायी जा रही थीं। ये नेपाल गये, नेपाल जाकर माओवादियों के साथ सीपीएम नेताओं ने बहुत सी बातचीत की। अब नंदीग्राम में अगर माओवादी पहुंच गये हैं। बंगाल में भी माओवादियों के कारण स्थिति खराब हो रही है। ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Md. Salim, you are the next speaker.

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can reply when you will speak. Now, please keep silent.

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded.

*(Interruptions) â€¦ **

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, नेपाल के माओवादियों से शस्त्र मिलते हैं, पैसा मिलता है। वहां से सब चीजें आती हैं जिससे देश भर में नक्सलवाद फैल रहा है, माओवाद फैल रहा है। आज उनका 160 से 180 जिलों में कब्जा हो रहा है। ये जिले धीरे-धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं परन्तु यहां पर केवल यह कह देने कि यह राज्यों का मामला है, ठीक नहीं है। जब तक केन्द्र सरकार राज्यों को पूरा पैसा न दे, उनको जितनी भी सहायता चाहिए, वे न दे, तो नक्सलवाद इसी प्रकार से बढ़ता जायेगा। वहां पर विकास के काम नहीं हो रहे, जिसके कारण भी नक्सलवाद फैल रहा है। परन्तु केवल इतना कह देने से कि थोड़े पथ-भ्रष्ट लोग हैं, अपने लोग हैं और इनसे बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। उनके साथ दोनों तरह का

---

* Not recorded

व्यवहार करने की जरूरत होगी। उनके साथ कठोरता का व्यवहार करने की जरूरत है। उनके खिलाफ लड़ाई के तौर पर जाने की जरूरत है और वहां पर विकास कार्य भी करने की जरूरत है। [MSOffice34]

15.00 hrs.

उपाध्यक्ष महोदय, यह मानना कि आतंकवादी केवल विदेशी हैं, पाकिस्तान से आते हैं या अफगानिस्तान से आते हैं या सूडान से आते हैं या तालिबान आते हैं, पर्याप्त नहीं होगा। हमारे अपने देश में भी धीरे-धीरे अल कायदा अपनी जड़ें जमा रहा है और अल कायदा यहां पर अलग-अलग जगहों पर फैलता जा रहा है। इस देश में भी उनके अड्डे कायम हो गए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मदरसे तो हैं ही जहां पर जेहादी मानसिकता के लोग पैदा होते हैं, किन्तु अब हमारे देश में भी खास तौर से बार्डर एरियाज में जितने मदरसे चल रहे हैं, उनके बारे में सावधानी रखने की जरूरत है। सरकार ने कुछ समय पहले एक टास्कफोर्स ऑन बार्डर मैनेजमेंट बनाई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था:

> "The Task Force has noted with concern the rapid spread of Madrassas and Mosques in the border areas on almost all borders. Most of these constructions have come up without any formal approval of the competent authorities. In several cases, considerable foreign funds have become available to these institutions through non-banking institutions. Efforts at Talibanisation of Muslims and their education are matters of concern which should not be dismissed light-heartedly. The intriguing thing is that these have come up where there is very

small or no population of minority community."

उपाध्यक्ष महोदय, इस कमेटी ने उनके बारे में यह भी कहा था:

"Talibanisation of Madrassas is taking place due to spread of fundamental ideology in these institutions. Madrassas in some places are reported to be sheltering ISI agents and subversive elements. "

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, उसके कुछ अंश जिन पर तुंत ध्यान देने की आवश्यकता है, उनको पढ़ रहा हूँ। इस समय पाकिस्तान में मदरसों को रजिस्टर किया जा रहा है, पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि मदरसों को रजिस्टर कराएं और उनकी पूरी निगरानी की जाए। अन्य कई मुस्लिम देशों में भी मुझे जाने को मिला है, वे भी अपने यहां के मदरसों के प्रति काफी आशंकित हैं और उन पर निगरानी रखी जा रही है, लेकिन हमारे देश में पहले मदरसों पर सरकार का जो थोड़ा-बहुत नियंत्रण था, वह भी हटा दिया गया है। पहले हमारे यहां एजुकेशनल संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती थी, अब उसे भी हटा दिया गया है। अब उनका न तो रजिस्ट्रेशन होता है और न कोई निगरानी होती है, उनके लिए न कोई नियम-कानून है, न तो वहां पर मॉडर्न एजुकेशन देने की बात सोची जाती है और न ही इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि वहां से जो लोग निकलते हैं वे देशभक्त बनें और अपने देश के प्रति वफादार रहें। इस प्रकार की कोई शिक्षा वहां पर नहीं दी जाती है।...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : मदरसों में देशभक्ति के खिलाफ भी कोई शिक्षा नहीं दी जाती है।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ram Kirpal Yadav, you are speaking without my permission. Please sit down.

जब आपकी पार्टी की भी बारी आएगी, तब अपनी बात कह लीजिएगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, बांग्लादेश इस समय आतंकवाद का बड़ा केन्द्र बनता जा रहा है। पाकिस्तान पहले से ही आतंकवाद का केन्द्र था और अभी भी है, परन्तु इस समय बांग्लादेश भी आतंकवाद का केन्द्र बनता जा रहा है। हमारे देश में इस समय जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उनके लिए जिम्मेदार जो आतंकवादी संगठन हैं, चाहे वह हूजी हो, जैश-ए-मोहम्मद हो, लश्कर-ए-तैयबा हो, अल कायदा हो या उल्फा हो, सभी की जड़ें और जन्मस्थल बांग्लादेश में है। इसलिए बांग्लादेश से बातचीत करते समय यह आवश्यक है कि इनके बारे में भी पूरी बातचीत की जाए और वहां पर जो आतंकवादी अड्डे बन रहे हैं, उनके समाप्त करने का प्रयास किया जाए। इसके बारे में उनसे सख्ती से बातचीत की जाए, परन्तु उनसे अभी तक जितनी सख्ती से बातचीत होनी चाहिए, वह नहीं हुई है। वहां से लोगों का हमारे देश में आना-जाना बहुत तेज हो रहा है। सरकार ने सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू किया था, लेकिन अभी तक 25 प्रतिशत एरिया में भी वह बाड़ नहीं लग पाई है और उसे रोका नहीं गया है। कई टेलीविजन चैनल्स में दिखाया गया है कि सीमा पर 100 रूपए खर्च करके आना-जाना कितना आसान है। अगर कोई आदमी 100 रूपए में सीमा के आर-पास आ और जा सकता है तो आतंकवादी भी इसी प्रकार से आ-जा सकते हैं और उनके लिए रास्ता खुला है। बांग्लादेश से होने वाली इस तरह की घटनाएं हमारे लिए बहुत चिन्ता की बात है, इसे रोकने के लिए भी प्रयास करने की जरूरत है। हमारे देश में बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है। इसकी वजह से करीब चार करोड़ बांग्लादेशी हमारे देश में आ गए हैं, अकेले दिल्ली में इनकी संख्या पांच लाख से ज्यादा है। ये आंकड़े पहले की गृहमंत्रियों ने दिए हुए हैं। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की लगातार चार जजमेंट्स आई और दिल्ली हाईकोर्ट की चार जजमेंट्स आई हैं।[R35]

उन सबमें कहा गया है कि वहां से होने वाली घुसपैठ हमारे देश पर एक हमला है, एक आक्रमण है, अतः इसे रोका जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर आप बांग्लादेश से घुसपैठ नहीं रोक सकते तो आपको राज करने का क्या अधिकार है, सरकार में बने रहने का क्या अधिकार बनता है, अगर घुसपैठ को आप नहीं रोक सकते। लेकिन पिछले चार वर्षों में कुल मिलाकर देखा जाए तो सैंकड़ों लोग भी नहीं होंगे, जिन्हें इस देश से वापस भेजा गया हो। हाई कोर्ट ने कहा था कि एक हजार लोगों को रोज भेजा जाए और सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरे चार करोड़ ऐसे लोगों को वापस भेजने की बात कही थी, जो यहां घुसपैठ के जरिए आ गए हैं तथा यहां पर आतंकवादी हमला करके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब करते हैं। इसलिए इस महत्वपूर्ण स्थिति पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष जी, हमारे लिए एक बड़े की संकट की बात यह है कि हमारी सेनाओं में आईएसआई की घुसपैठ हो रही है। यहां पर 23 अक्तूबर को तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर प्रणव मुखर्जी साहब ने बयान दिया था। I would like to quote what Shri Pranab Mukherjee told reporters:

"The Armed Forces would conduct internal investigations to ascertain the extent of Pakistan's Inter Services Intelligence (ISI) penetration into the Indian armed forces, and its likely impact. It is a matter of concern that the ISI is trying to infiltrate and subvert our armed forces."

हमारे जो सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने भी कई बार इसका उल्लेख किया है। उसके बाद जम्मू-कश्मीर में भी दो आदमी सेना के पकड़े गए, जो यहां से जानकारियां बाहर भेजने का काम कर रहे थे। उसके बाद माना गया कि सेना में भी आईएसआई घुसपैठ कर रही है। इस बारे में क्या कदम सरकार ने उठाए हैं और उसे रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, यह मंत्री जी बताएं? लगता है कि मामला उल्टा हो रहा है, यहां पर पिछले दिनों बड़े जोर-शोर से घोषणा की गई। चाहे सच्चर कमेटी हो, चाहे प्रधान मंत्री जी का 15 सूत्री कार्यक्रम हो या प्रधान मंत्री के विशेष सेल की बात हो, जिसके द्वारा मानिटर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सेना और अर्धसैनिक बलों में अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों की बड़ी तादाद में भर्ती हो रही है। इस बात पर संतोष व्यक्त किया गया है। अगर योग्यता के आधार पर किसी की भर्ती हो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बिना योग्यता के, केवल धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर भर्ती हो और उसके लिए विशेष अभियान चलाकर प्रयास किया जाए कि उन्हीं की भर्ती ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे उनका अनुपात बढ़े, तो यह सीधे-सीधे आतंकवाद को न्यौता देने जैसी बात है। इससे यह

लगता है कि वे लोग यहां आएं और हमारी सेनाओं तथा अर्धसैनिक बलों में भर्ती हों। एक प्रकार से उन्हें खुली छूट दी जा रही है। अगर इस प्रकार से होता रहा तो सेना भी बंट जाएगी, उसमें भी आईएसआई को आने का मौका मिल जाएगा। अगर आप समझते हैं कि आतंकवाद का ठीक प्रकार से मुकाबला किया जा सके, तो आपको दो-चार काम तुंत करने की आवश्यकता है।

सबसे पहले तो एक ऐसा आतंकवादी, जिसने हमारी इस संसद पर, जिसे देश का दिल कहा जाता है, जो जनतंत्र का मंदिर है, उस पर हमला करने वाले अफजल को फांसी दी जाए। इस सजा का फैसला सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, लेकिन दस महीने हो गए उसकी फांसी पर अभी तक रोक लगी हुई है। इससे आतंकवादियों को लगता है कि अगर वे कोई वारदात करेंगे तो पहले तो उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा। अगर पकड़ भी लिया गया तो जमानत पर छूट जाएंगे। अगर नहीं छूटेंगे तो सजा होगी, वह मिलेगी नहीं। इसलिए पहले आप अफजल को फांसी दीजिए। इससे अन्य आतंकवादियों को एक मैसेज जाएगा कि यह सरकार उनके खिलाफ लड़ने के लिए तत्पर है और किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगी।

दूसरी बात यह है कि पोटा से भी ज्यादा सख्त कानून बनाया जाए। मैंने पहले भी कहा था कि आतंकवाद देश के साथ विश्वासघात है। अपने संविधान की रक्षा करने की आपने शपथ ली है और संविधान को नुकसान पहुंचाने के लिए जो लोग आ रहे हैं, जो पैसा उनके द्वारा हमारे बाजार में लग रहा है, उस पैसे को पोटा द्वारा ही रोका जा सकता था। लेकिन अब वह कानून नहीं है और साधारण कानून में अगर इस तरह का पैसा पकड़ा जाए तो उस व्यक्ति को जमानत मिल जाती है। इसलिए पोटा से भी सख्त कानून की आवश्यकता है। इसका इंतजार न करें कि देश में कितनी और ऐसी घटनाएं होंगी, तब आप सोचेंगे कि ऐसा कानून आवश्यक है। यहां पर वित्त मंत्री जी द्वारा भी आतंकवादियों द्वारा स्टाक मार्केट में धन लगाने की आशंका जताई गई। इसलिए स्टाक मार्केट और अन्य वित्तीय संस्थाओं की कड़ी निगरानी की जरूरत है। पिछले कई वर्षों से लगातार कहा जा रहा है कि हमारे देश में बड़ी संख्या में जाली नोट आ रहे हैं। [R36]

जाली नोट दूसरी जगहों से आते हैं और कई बार पकड़े भी जा चुके हैं। जाली नोट चलाकर हमारे देश की आर्थिक स्थिति को बर्बाद करने का यह एक बहुत बड़ा षडयंत्र है। हमारे स्टॉक-एक्सचेंजेज में आंकड़े चढ़ते-चढ़ते आज 19000 से ऊपर चले गये हैं, उनका पैसा इनमें लगा है। कल माननीय चिदम्बरम साहब ने माना है और इसके बारे में ज्यादा कठोर कार्रवाई करने की जरुरत है। पाकिस्तान और बंगला देश के जो आतंकवादी अड्डे हैं इन्हें समाप्त करने की सख्त चेतावनी दी जाए और जब तक वे ऐसा न करें, तब तक उनसे बातचीत बिल्कुल न की जाए - यह भी बहुत आवश्यक है।

मदरसों पर कड़ी निगरानी की जाए, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। बंगलादेशी घुसपेठियों को देश से निकालने के लिए कठोर पग उठाए जाएं

SHRI J.M. AARON RASHID (PERIYAKULAM): You have to speak about the Godhra incident also....(*Interruptions*) Do not drag Madam Sonia Gandhi in this matter....(*Interruptions*) Shri Modi has said in a public meeting that the Zorabudin muder is legal. But it is wrong. Action has to be taken against the real culprits....(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I know. Please sit down. He is going to conclude now.

श्री जे.एम.आरुन रशीद : 40 मिनट से ज्यादा बोलते इन्हें हो गये हैं, हमें भी बोलना है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

...(*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, मैं समाप्त कर रहा हूं, और ज्यादा तकलीफ इन्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी बातें, जो मैं कह रहा हूं, बहुत ज्यादा इन्हें चुभती हैं। उपाध्यक्ष जी, मैं आरोप लगाता हूं कि यह सरकार आतंकवाद के प्रति बहुत नरम है, यह एक तरह से हमारे देश के ऊपर आक्रमण हो रहा है और उस आक्रमण का मुकाबला करने के बजाए, हम शतुरमुर्ग की तरह आंख बंद करके बैठे हैं - अपने वोट बैंक के लिए, अपनी राजनीति के लिए, चंद वोट लेने के लिए। अगर हम देश के हितों के साथ इसी तरह से विश्वासघात करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं।

SHRI NIKHIL KUMAR CHOUDHARY (KATIHAR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak on this subject.

Sir, this august House is discussing the situation of internal security. I must begin, first, by saying that the condition of internal security in the country has never been better. I say this with a full sense of responsibility and knowledge.

I know there have been instances of terrorist nature. But if we were to go back in time, we will see that the number of such incidents has come down, the areas affected by such instances have also shrunk and there is every indication that the administration is fighting a winning battle against terrorism.

I would just like to go back to the situation in Punjab in the 1980s and till the mid-1990s. It appeared that terrorism would tear this country apart. It was a serious threat. Still, we were able to ride the wave of terrorism, restore normalcy in Punjab. If we did that, it was entirely because we followed a democratic process. We encouraged a democratic style of Government. I remember that the Punjab Chief Minister became a martyr to the cause of restoring peace in the strife-torn State. He was assassinated. But his assassination proved to be a wonderful contribution to the cause of peace in this country and in the State of Punjab. Even in Jammu and Kashmir, which has seen terrorism for a very long time – almost now two decades – we are in a position to win this war. If we are going to win this war, it is once again because of a process of democratic functioning that has been there for some time now. It is this democratic functioning that gives the people of the State, the people of this country an inherent faith in the administration.[R37]

It is commonly believed that terrorism feeds on causes of discontent. If these causes are addressed in time, then no

amount of terrorist activities will mislead the public. People will have an inherent faith in the quality of governance and it is this feeling which will enable them to remain quiet and see how the events unfold themselves. When I say all this, especially with reference to the situation in Punjab in 1980s and now in the State of Jammu and Kashmir, I am conscious of the fact that no special laws had proved to be effective in controlling the situation. We have heard enough in this hon. House about how special laws will bring about this, will bring about that improved in the situation. I am personally aware of what laws can do and what special laws can do. So much is being said about special laws.

It was the Government of 1984-89 that first thought that special laws would be an important aid to combat terrorism and TADA was passed. Then, unfortunately and tragically, TADA was enforced. At that time even, there were host of such terrorist acts that took place all over the country. They could not be brought under control; they could not be prevented. My question is what those special provisions were in a special law that could not help the administration to prevent terrorism. The administration could not control terrorism. Now, what are those provisions which are not available even now under any of our laws? It is this which has become a matter of question mark. That is why, there is no special law. Special law, if it is necessary, will most certainly be brought in. Special laws, however, have been found not to be of any great assistance in aiding or assisting the administration, in controlling and combating terrorism.

There is one other matter about special laws that this House and the whole country should take notice of. It is because it is considered to be a special law, there is a feeling among most of the law enforcing authorities that they can get away with it. It is this psychology that led to massive misuse of TADA. Therefore, at the time, when it needed to be renewed, it was allowed to lapse and it was in April, 1995, that the then Government decided not to renew, not to extend it and not to give it a fresh lease of life and TADA was allowed to lapse. Six years later POTA was brought in. I would only like to ask what POTA gave us. What has POTA contributed to combating terrorism in this country in a very effective manner? What has POTA got in its provisions that, let us say, any other general law does not have. But, the law enforcing authorities are not in a position to use it to combat terrorism. Unless we address these questions as to what are the provisions in a special law which are helpful to the Government, to the administration and to the law enforcing authorities to combat terrorism effectively that we will get an answer. It does not quite help. If you just go on harping that there should the special law, after all, there were assassinations of so many people with even TADA. It was in the wake of the assassination of our late Prime Minister, Shrimati Gandhi that this Act came so that such tragic incidents could never happen in the future. It did not do tha[MSOffice38]t.

Let us once and for all settle this matter and allow it to rest in peace that special laws are not necessary. On the other hand, whatever provisions which are already available to us in our general laws are quite adequate for any enforcing authority if it deals with this matter in a sincere manner to combat terrorism and combat terrorism very effectively.

Sir, only the other day, the hon. House was discussing the instances of bomb blasts in Uttar Pradesh. My dear colleague Shri Rajesh Verma is not here now. He mentioned that the Central intelligence agencies had not advised the Government of Uttar Pradesh about this impending strike. I would like to remind our dear colleague that it is in Uttar Pradesh that a wonderful piece of investigation and detection was done when some terrorist organisation was planning an assault on our young Member of Parliament Shri Rahul Gandhi and much was made of the ability of the CID and Intelligence Wings of the UP Police in having been able to unearth this sinister plot. We all compliment the UP Government on this wonderful work and this work was done entirely by the UP Police itself. It claimed credit for that and we are proud to give credit. In the case of these bomb blasts, I would like to make it clear that there are two types of intelligence collection. I am sorry I am veering around into some kind of professional dissertation, but this is a fact which needs to be understood by this hon. House.

The Central intelligence agency is obliged to advise and alert the State Governments about an impending strike. But any strike that takes place is brought about only with the assistance of local people. Unless there is local assistance, unless there is complicity or involvement of the local people, no terrorist strike can take place and so, which are the people involved and who are in complicity with these terrorist organisations is for the local intelligence agency to find out and the UP Government has an excellent arrangement in having a local intelligence unit in every district. It is this unit which identifies the people who are supposed to be in league with or in complicity with terrorist organisations. Once an advice comes from the Centre to be prepared and to be alert, it is these units which are supposed to work and collect intelligence that should go to prevent such strikes. So, I am not saying that the UP Government is to be blamed or the UP Government has failed or some such thing because I have already complimented and paid tributes to the UP Government for unearthing that sinister plot. Therefore, it is not necessary to blame the Central intelligence agency of the Central Government for what is basically a job that has to be done at the local level, at the district level.

The other point is something that was mentioned very rightly by Prof. Vijay Kumar Malhotra, that is the threat of naxalism.

I really feel that the threat of naxal activities today is even more serious and sinister than the threat posed by terrorism which is imported from across the border. I would like to go back to the time when India gained Independence. It was at that time that we chose to ourselves a parliamentary system of democracy, a parliamentary system of governance. We did that in the hope that we will be able to identify people's grievances, sit down with them, obtain their views, obtain their difficulties and take suitable measures to redress them. It amounts to a question of governance. This governance has been lacking in this country and it is this lack of governance which is being exploited in the form of ideology. The ideology does say that there should be socio-economic equality, there should be removal of rural inequality and there should be removal of the divide between rural and urban areas.[R39]

[r40]Prosperity must go to the countryside because, indeed, India lives in its villages and unless the villages of this country are prosperous, unless they are in a position to have access to resources, India will never improve. It will never develop. So, it is a lack of development in the rural countryside, which is the basic cause of Left Wing extremism in the country.

Having said that we must also now see as to why it has not been possible to redress grievances of our people living in the rural countryside. It is not that we have not been able to identify measures to redress the grievances. It is not that the Centre, particularly, the present UPA Government has not identified socio-economic, social security and other such welfare schemes. There are host of them. It is also not that the Central Government has not been giving funds.

Prof. Vijay Kumar Malhotra mentioned that there should be no hesitation in giving funds to the States regardless of the political colour and complexion of the State Government concerned. This has been done. I do not wish to cast aspersions on the State Government concerned, but I just cite one instance. There is one very interesting scheme, the Indira Awaas Yojana, which seeks to give a roof over the heads to all people who are below the poverty line. In my home State, Bihar, Rs.600 and odd crore were given. Why is it that less than 50 per cent of that has been so far utilised in this entire financial year of 2006-07?

This Government conceived of an excellent scheme which if implemented would have gone a long way, if not in removing poverty, in certainly reducing poverty in the countryside. I am speaking of the National Rural Employment Guarantee Scheme. Once again I cite the instance of Bihar. In the whole financial year of 2006-07, more than adequate funds were given to the State, but by the end of the financial year less than 35 per cent of the funds have been spent.

Now, this is something that needs to be understood and appreciated as to why the State Government is not in a position to spend the money that has been given to it by the Centre. We have been talking about there being a need, as was made out at the time of last election, of *bijli, sadak, pani*. Under the Prime Minister's Gram Sadak Yojana and the then Rashtriya Sam Vikas Yojana, which has now been renamed as the Backward Region Development Fund, hundreds of crores of rupees have been given to the States. Roads are being built by the Central agencies, for instance, IRCON, but still it is not enough. The roads will have to be made also by the State Governments. Why is it that the roads which are supposed to be built by the State Governments are not being built?

The question does not arise of the Centre giving funds to the State Governments for building of roads which come under the purview of the State Governments. If the State Governments ask for it, perhaps, the Centre will immediately comply and provide the necessary funds, but whatever funds have been given, they are not being used.

I shall cite to you another very pathetic instance, extremely pathetic instance. People who live below the poverty line, who do not have enough means of livelihood to themselves a wonderful scheme has been conceived of giving them pension, pension for those who are under the old-age scheme and who are deserving of social security. Once again, hundreds of crores of rupees have been given to the State Government and I am aware and I say this with my personal knowledge of my own constituency. This money is not being spent. People are not being given the pension that are supposed to be given. Why is this?

The question does not arise of what Prof. Vijay Kumar Malhotra said that funds should be given. Funds are being given, but if the funds that are being given are not being utilised to the maximum extent by the State Governments, something is wrong in the State Governments concerned and it is a question of poor governance. We need to improve this poor governance.[r41] We need to improve our quality of governance; we need to give our people good governance. I would suggest that one important aspect which has an impact on the public mind is the need for immediate redressal of their grievances. It could relate to any kind of dispute. It could be a dispute relating to land; it could be a dispute relating to money-lending; it could be a dispute relating to some crime. What happens is that it is in the criminal justice system that the people look for redressal and succour. This takes a lot of time. It is this which is being exploited by the Left Wing extremists. They hold *jan adalats*. The impression that is given to the public at large is: "Do not go to the criminal justice system. It will not give you justice. Not only will it be very expensive, which you cannot afford; it will take a long time. Here

we are. We will give you ready justice." Indeed this is being done. Why cannot the Administration, why cannot this Government of the day itself do something resembling a *jan adalat*? I would suggest that the Government may consider holding local courts in a fast track mode at the level of at least sub-divisions, if not *prakhands* meaning blocks. If it is difficult to hold them at the *prakhand* level, hold them at the sub-division level. But, hold them, by turns in the *prakhands*. That is going to give a great deal of relief to the people, to the poor who have a lot of grievances.

The second thing is that we keep talking of landless people. Why are these landless people not being given land that they should be given? There is a regular scheme of being given, awarded, allotted land to the landless. There is in my district, for instance, an identification of people who are below the poverty line, who are landless and who should be given land. A number of these people exist on that list. But, why is it that the Government of the day in Bihar and the district administration is not in a position to distribute that land? I would suggest that this is a serious matter and even though it happens to be within the ambit of a State Government, our Central Government should take the initiative and get the State Government to report progress in the question of distribution of land.

I wanted to say some more things but, I think, these two suggestions regarding good governance especially with reference to criminal justice system and holding of something akin to a *jan adalat* at the sub-divisional level should be taken note of. The other thing is about redistribution of land to the landless.

I would now like to invite the attention, through you, to the Government to a problem that is developing in our North-Eastern State of Mizoram. I have been there. I spent time there. There is a peculiar phenomenon. It takes place almost every 50 years. It is called *motham*. There is a special brand, special quality of bamboos that grows every 48-50 years. When rats, rodents, bugs feed on them, their reproductive powers increase and their population multiplies several times, several fold, and they eat up all the available food and crops. This happened in 1916; it happened in 1966; and it is now going to happen in 2007-2008. It happens almost 50 years. Already, I have found out that the crop in Mizoram is very poor. There has been hardly any cultivation in the past two years. It is time that the Central Government woke up to this very serious threat and redress people's grievances by making it possible for the Centre to provide whatever food, whatever foodgrains etc. are needed by the people. This supply of foodgrains to the State of Mizoram must be organised without any delay. It should be done effectively. If it is not done, then we will go back to the spectre in 1966 when a serious threat emerged with the formation of the Mizo National Front, an under-ground organisation, and for 20 years that organisation held the Central Government at bay. Had it not been for Rajiv Gandhi's foresight and commitment to integrity or maintaining integrity of this nation, we would not have been able to sign a deal with Shri Laldenga.[r42]

It was done in 1986. Thereafter, that State is peaceful. Thereafter, that State has not been a threat to the integrity of this country. That kind of threat is very likely to happen now and it is time that the Central Government woke up and saw to it that necessary steps for the redressal of people's grievances in Mizoram are taken.

Sir, I am very grateful to you for having given me so much of time.

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता - उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा हुआ श्री निखिल कुमार जी, मेरे पूर्व वक्ता को पेशेगत रूप से अनुभव भी है और सांसद के रूप में भी अनुभव है...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिये मैंने उन्हें 25-26 मिनट बोलने के लिये दिये हैं।

मोहम्मद सलीम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जब यहां आंतरिक सुरक्षा की बात की गई है तो एक तरफ से दूसरी तरफ और दूसरी तरफ से तीसरी तरफ ये लांछन लगाते हैं। हम लोग समझ जाते हैं कि आंतरिक सुरक्षा हमारे देश की चिन्ता है। आंतरिक असुरक्षा बढ़ रही है, कारण कि चुनाव में हम लोग एक दूसरे के प्रति अपने पाइंट स्कोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग चिन्तित है।

उपाध्यक्ष महोदय, जुलाई महीने के बाद हम लोकतांत्रिक तरीके से इस संसद में इस माहौल के बारे में बातचीत कर रहे हैं । देश की आजादी के 60 साल बाद ऐसा पहली बार छत्तीसगढ़ में हुआ। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वहां असैम्बली में, इन-कैमरा तो छोड़िये, मीडिया और असैम्बली के कर्मचारी तक को बाहर रखा गया और असैम्बली में एक स्पैशल सैशन चलाया गया। यह चर्चा करीब-करीब पौने आठ घंटे तक चली। इस चर्चा में आई.जी., चीफ सैक्रेट्री, डी.जी., और होम सैक्रेट्री ने भाग लिया। चूंकि विषय की गम्भीरता थी, इसलिये मैं इस पर और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि देश में ऐसी स्थिति नहीं कि संसद में भी ऐसी चर्चा कभी करनी पड़े। हालांकि अध्यक्ष महोदय के स्पेशल रूल बने हुये हैं, स्थिति के अनुसार कभी भी कर सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ असैम्बली में ऐसी स्थिति बनी। यह केवल उस स्टेट का मामला नहीं है, यह सारे देश का मामला है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कोहिमा तक, कहीं ज्यादा, कहीं कम, कभी एक जिले में ज्यादा हो जाता है तो दूसरे जिले में कम हो जाती है, कभी किसी स्टेट में कम तो कभी किसी स्टेट में ज्यादा होता है। आज देश में सुरक्षा का अभाव पैदा किया जा रहा है। मेरा कहना है कि हम अलग-अलग संगठन के लोग देखते हैं। अक्सर माओवादी मामला होता है या दूसरी तरफ टैरिरिस्ट्स हमला हो रहा है, बम विस्फोट हो रहे हैं। अभी कुछ समय पहले वाराणसी, लखनऊ और फैजाबाद में बम विस्फोट हुये हैं। मैं इन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। नार्थ ईस्ट स्टेट्स, जम्मू कश्मीर में मिलिटैंसी वर्षों से चल रही है। लोगों की जानें जा रही हैं। जब कभी हम संसद में प्रश्न करते हैं तो मंत्री महोदय जवाब देते हैं कि कभी आंकड़े बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि एक कहता है कि आपके जमाने में ऐसा हुआ तो दूसरा कहता है कि नहीं, आपके जमाने में हुआ। लेकिन ऐसा काफी समय से हो रहा है। मैं समझता हूं कि आंतरिक सुरक्षा के मामले में एक होलिएस्टिक अप्रोच होनी चाहिये। इसमें

बोलना आसान है मगर दिक्कतें ज्यादा हैं। राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और विभिन्न राजनैतिक दलों को इस पर बहस करनी चाहिये लेकिन एक होलिएस्टिक अप्रोच होनी चाहिये। जैसा कहा गया कि माओवादी घटनायें देश के कई प्रान्तों में हो रही हैं, उस संगठन का यूनिटरी कमांड सिस्टम है। देश में पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, आध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में ऐसी घटनायें हो रही हैं। सरकार जो अपनी रणनीति बनाये, उसे टोटैलिटी से तैयार करना पड़ेगा।[s43]

दूसरी बात यह है कि सुरक्षा की जो भावना है, मैं वीवीआईपी सुरक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, वह बेशक बहुत ज़रूरी है, हमारा संसद भवन टैररिस्ट अटैक के बाद और ज्यादा सिक्योर हुआ है लेकिन आम जनता के मन में सुरक्षा के क्या भाव हैं, वह हमारे लिए इंडीकेटर है। वह भावना कभी घटती है तो कभी बढ़ती है। कभी कभी दिवाली, रथ यात्रा, ईद और रमज़ान के महीने में या और पर्वों पर हम रैड अलर्ट घोषित कर देते हैं जब सुरक्षा की भावना लोगों में कम होती है। उसके लिए जो रिस्क एनालिसिज़ है, जैसे वीआईपी का थ्रैट पर्सैप्शन हम देखते हैं और सुरक्षा के प्रावधान कम या ज्यादा करते हैं, उसी तरीके से पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जिलों में अलग अलग लोगों का, भारतीय नागरिकों का रिस्क एनालिसिज़ होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि एक डाटा होना चाहिए। डाटा है, लेकिन मॉडर्न नहीं है। हम आई.टी. में पूरी दुनिया के लीडर हैं लेकिन हमारे जो रीयल डैटा कलैक्शन्स हैं, जो एक्शनेबल इंटैलिजैंन्स हैं, जिस पर हमें एक्शन लेना पड़ेगा, उसमें अलग अलग एजेन्सीज़ काम कर रही हैं, जिनके बीच कोआर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू-कश्मीर में और नक्सल अफैक्टेड एरियाज़ में बम विस्फोट होते हैं। कहीं लैन्डमाइन ब्लास्ट होते हैं, कहीं पावरफुल बम एक्सप्लोड होते हैं। फिर हमारे देश में आरडीएक्स आया और अभी आई.ई.डी आ गया है। लेकिन जब स्टेट पुलिस की तरफ हम देखते हैं तो उनके बम डिसपोज़ल स्क्वैड्ज़ वही हैं। वे क्या करते हैं कि कहीं कोई पेटी रखी है और उनको खबर दो, वे आएंगे और देखेंगे, कुत्तों से सुँघाएंगे, बाल्टी लेकर आएंगे और उसको डिफ्यूज़ करेंगे। उसकी टैक्नोलॉजी अब बदल गई है। उसके लिए कुछ लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ हमारे देश में उस पर काम हो रहा है। अभी जब हम पढ़ते हैं कि कैमिकल विस्फोट होते हैं, उसमें नाइट्रेट वगैरह होता है। ये जो आई.ई.डी. है, उससे हम कैसे निपट सकते हैं यह भी देखना है। फिर अक्सर ऐसा होता है कि कहीं कोई पकड़ा गया तो अलग बात है लेकिन अभी हमने देखा फैज़ाबाद वगैरह में कि जब ब्लास्ट हो जाता है तब खबर मिलती है। तो हमारा पोस्ट ब्लास्ट मैकैनिज़्म कैसा है, हम फिर बम डिसपोज़ल स्क्वैड क्यों बुलाते हैं पुलिस का? पुलिस के पास तो विस्फोट होने से पहले उसको डिफ्यूज़ करने की ट्रेनिंग है लेकिन जब विस्फोट हो जाता है तो उसके बाद क्या करना है, किस तरह से डैटा कलैक्ट करना है, किस तरीके से एविडेन्स कलैक्ट करना है, किस तरीके से साइंटिफिक तरीके से उसका एनालिसिज़ करना है, किस तरह से उसके सुराग को एस्टैबलिश करना है? हम अगर देखते हैं तो पिछले कई सालों से जो विस्फोट हो रहे हैं, अखबारों और टेलिविज़न में हम जो रिपोर्टिंग देखते हैं, आजकल तो टैलिविज़न में भी एक्सपर्ट्स हो गए हैं। लोग साथ-साथ दो मिनट में संस्था का नाम बोल देते हैं कि कौन जिम्मेदार है, वह भी बोल देते हैं। फिर रिपोर्टर्स उसको लिखते हैं। मैं अभी आंकड़े इकट्ठा कर रहा था तो देखा कि जितने विस्फोट हुए हैं, उसके बाद एक ही तरह की रिपोर्ट्स अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों से आती हैं लेकिन वे छप जाती हैं। सूत्रों के बारे में कहा जाता है कि कहीं पुलिस का सूत्र है, सरकार का सूत्र है, इंटैलिजैन्स का सूत्र है, मंत्री महोदय का सूत्र है, ऐसा बोल देते हैं, लेकिन हर विस्फोट के बाद कहा गया कि सुराग मिल गया, लोग पकड़े गए, मामला आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज तक एक भी विस्फोट का अभियुक्त पकड़ा नहीं गया, चाहे मक्का मस्जिद विस्फोट ले लो, मालेगांव ले लो, मुम्बई ब्लास्ट ले लो, अजमेर की दरगाह शरीफ ले लो, चाहे वाराणसी ले लो, संकटमोचन मंदिर में ले लो या अक्षरधाम मंदिर में ले लो ...(व्यवधान) मैं जनप्रतिनिधि के नाते हमारे यहां की व्यवस्था बता रहा हूँ। कोई खबर होगी तो आपको लगेगा कि यहां तो मोहम्मद सलीम के खिलाफ बोला जा सकता है तो बोल दो, कोई खबर में, मुझे लगेगा कि उनके खिलाफ बोला जा सकता है तो बोल दो। ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Salim, please address the Chair.

â€¦(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह : ये चेयर को निशाने पर नहीं रखना चाहते। ...(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : मैं कह रहा हूँ कि कोई भी इसको अपने तरीके से, पीसमील तरीके से रंगीन चश्मे से देखकर बयान कर सकता है। ...(व्यवधान) लेकिन सुरक्षा की जो भावना है, उसके लिए हमें आंकड़े इकट्ठे करके सामने आना चाहिए। हमें नेशनल बम डैटा देखना चाहिए कि कहां कहां क्या विस्फोट हुए, किस तरह के विस्फोटक इस्तेमाल किये गये, उसके डैवलपमैंट्स क्या हो रहे हैं।[h44]

यह माडर्न मेनेजमेंट का तरीका है। मैं कोई पोलिटिक्स नहीं कर रहा हूं, अगर आपको किसी चुनौती से निपटना है तो आपके जो साधन एवं संसाधन हैं, उन्हें आपको एकत्रित करना पड़ेगा। हम कम नहीं कर रहे हैं, मंत्री जी जवाब में फिर कहेंगे। इसमें चाहे माओइस्ट, आतंकवादी या मिलिटेंसी हो, चाहे आर्गेनाइज़्ड क्राइम जो हो रहे हैं, उनके बारे में यह भावना है कि ठीक है हिरोइज़्म काम करता है। पुलिस के अंदर भी हमारे यहां कॉप से सुपर कॉप होते हैं, उनके हाथ में बन्दूक दे दो और वह अंधाधुंध दनादन क्नाट प्लेस में गोली चला देगा। उसे मीडिया हिरोइज़्म बना देता है। उसे इलैक्शन चैनल में बुलाया जा सकता है। हम कभी-कभी कहते हैं कि हमारे डीजीपी ने ऐसा किया और उनके आईजीपी ने वैसा किया। उन्हें वहां से यहां ले जाओ तो वे सब ठीक कर देंगे। इसे मेच्यो बोलते हैं। हिन्दी फिल्म और हॉलीवुड, बॉलीवुड में जैसे होता है, वैसे ही हम रिअल टाइम में भी कभी-कभी मिलिटेंसी, आतंकवाद और ऑर्गनाइज़्ड गैंग से निपटने के लिए उसका विज़ुअल अपील भी होता है और न्यूज़ वेल्यू भी होता है या कुछ दिनों तक जब वे सर्विस में रहते हैं या जब कोस्ट गार्ड होता है, यह डेवलप कर रहे हैं। वे कभी-कभी क्लिक कर जाता है और कभी-कभी नहीं करता है। श्री के.पी.एस. गिल साहब, ठीक है, वे बहुत अच्छे हैं। उनका पंजाब में कंट्रीब्यूशन भी रहा है। ठीक है, हम कहेंगे कि उनका मैच्यो है। जब उन्हें हम छत्तीसगढ़ में ले आते हैं, ट्रांसफिरंट कर देते हैं तो वहां भी मामला हो जाएगा। यह मेच्यो की भावना है। अगर ये फिल्म उस हीरो के चलते ठीक हो गई तो फिर दूसरे डायरेक्टर ने उस हीरो या हीरोइन को साइन कर लिया तो वह भी चल जाएगा।...(व्यवधान)

महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूं।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Silence please.

Please address the Chair.

मोहम्मद सलीम : दूसरी बात यह है कि मेच्यो सेवा भावना है। लोग यहां बोलते हैं कि यह पोलिटिकल हो जाएगा।पुलिस से पूछो तो वे बोलते हैं कि और भी कड़े से कड़ा कानून बनाना चाहिए तो वह भी एक मेच्यो की भावना है। हमारे ऊपर हत्या कराने का, थोड़ा थर्ड ग्रेड करने का, थोड़ा पीटने का, थोड़ा फांसी देने का कानून हो जाए तो हम अरेंज कर देंगे, लेकिन आप पूरे विश्व में देखिए कि लोगों में असुरक्षा की भावना और चुनौती बढ़ रही है और इसके साथ-साथ आतंकवादी मामला भी

पूरा फैल रहा है। साऊथ एशियन में भी देखें, बंग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी ऐसे ही हो रहा है, उसका प्रभाव हमारे देश में पड़ रहा है। इन आइसोलेशन नहीं, मैंने जिले से शुरू किया था, लेकिन जियोपोलिटिकल सिचुएशन है। पूरे विश्व का, हमारे पूरे साऊथ एशियन का, हमारे देश का, उसके आधार पर आपको यह आंतरिक सुरक्षा के मामले में, उस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा, न कि अगले साल यहां चुनाव है और उसमें कौन हमारे पक्ष में है और कौन विपक्ष में है। यह बोलना आसान है, बोलते हैं कि वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, अगर टाडा, पोटा लेकर वोट बैंक की राजनीति होती तो टॉडा बनाने वाली कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है, वे हारते नहीं। टॉडा दिखाकर जीतते रहते, वोट बैंक पॉलिटिक्स पोटा बनाने वाली बीजेपी के बारे में बोल रहा हूं। पोटा था तो फिर वोट में नहीं हारते, उसका उलटा समझते हैं कि नहीं ये पोटा, टाडा के विरोध में कर रहे हैं तो ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। ये वोट वाला बैंक कोई एसबीआई वाला एकाउंट नहीं है, एटीएम कार्ड नहीं है कि आप जाओ और ले लो। आपका वोट धड़ाधड़ निकलता जाएगा। उसे हम बहुत सिम्पलीफिकेशन करके देखते हैं और लांछन लगाते हैं। तीसरी बात यह है कि मेरा यह पहला पैराग्राफ था कि हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी अगर देश को देनी है तो उसके लिए हमारी एक स्ट्रेटजिक सोच चाहिए और राजनीतिगत एप्रोच और परिवर्तन सोच में चाहिए, फंडामेंटल परिवर्तन चाहिए। रिस्क तो है और रिस्क एनालिसिस जिस तरह से होगा उसके ऊपर रिस्क मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अगर हम सोचते हैं पुलिस ऑन द स्टीक सिर्फ वे करें तो गलती हो जाएगी। चाहे राजनीतिक नेता हों, एन्जीक्यूटिव्स या पुलिस बल हों, हम सबको अपने-अपने तरीके से वहां इनपुट डालना पड़ेगा। अभी निखिल जी बोल रहे थे। प्रधानमंत्री जी का भाषण है और मैं भी बोल रहा हूं, हमारी सोच भी बदलती रहती है, मैं सोचता हूं कि थोड़ा अनुभवी हो गया हूं। अगर हम डेवलपमेंट को एड्रेस नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़, में दांतेवाड़ा, आंध्र प्रदेश या वैस्ट मिदनापुर, बांकुरा, पुरुलिया जौन या अन्य जगह को देखते हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, ट्राइबल बैलट,...(व्यवधान) यह हंसने की बात नहीं है...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): नंदीग्राम को भी देखना चाहिए। ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No disturbance please. [rep45]

15.50 hrs.

(Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair)

मोहम्मद सलीम : आप अगर समझते हैं कि नन्दीग्राम के बहाने आपको असैम्बली में एक एम.एल.ए. की सीट मिल जाएगी, तो गलत है। यह उतना आसान नहीं है। हमारा अनुभव आपको छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लड़ने और माओवादियों से लड़ने में काम आएगा। हमें अनुभव है। आज इसे आप खींच रहे हैं। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ बोल रहा हूं। मैं बोल रहा था कि स्ट्रैटैजिक सोच बदलनी पड़ेगी, यह ज्यादा जरूरी है। मैं बोल दूं और आप सुन लें, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद, उस स्ट्रेटैजी के एन्जीक्यूशन का मामला है। एन्जीक्यूशन के मामले में, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों काम करें। इसमें कोआर्डीनेशन की जरूरत है। आप स्वयं देख लो, यदि माओइस्ट को आप छत्तीसगढ़ में पनपने दोगे, यदि झारखंड में पनपने दोगे, तो क्या बंगाल और उड़ीसा की सीमा महफूज रहेगी, कभी नहीं रहेगी, क्योंकि वे तो बॉर्डर एरिया में करते हैं। आर्गेनाइज्ड क्राइम जो होते हैं, वे दो थानों के किनारे में होते हैं या दो डिस्ट्रिक्ट के किनारे के थानों में करते हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं, जो बॉर्डर लाइन है, फिर चाहे वह अन्तर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो, उससे मिलिटेंट्स को फायदा होता है। जो स्टेट के बॉर्डर्स हैं, वहां इंटरनल सिक्योरिटी के जो थ्रैट्स हैं, वे करते हैं। आप खुश हो सकते हैं कि हमारी सीमा की बजाय उनकी सीमा में हो गया है। अगर आप सिर्फ छत्तीसगढ़ देख लें, सरकार के पास आंकड़े होंगे, क्या स्थिति है? एक जिला दांतेवाड़ा जिसके 65 हजार लोग, उनमें अधिकतर ट्राइबल्स हैं, यह पार्टी, वह पार्टी नहीं, वे गांव से बाहर हैं, जिले से बाहर हैं। इंटरनल मायग्रेशन हुआ है। ड्यू टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रैट से 65 हजार लोगों ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पनाह ली है। क्यों, क्योंकि वे सलवाजुडूम में जुड़ गए थे। आपने कहा कि ट्राइबल बॉयज को पुलिस अफसर बना दिया, दो-ढाई हजार रुपए दे दिए, और माओइस्ट ने रिटैलिएट किया। गांव वाले तो गांव छोड़कर भाग गए। इस साल 42 हजार हैक्टेयर जमीन में खेती नहीं हुई। मैं छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़े बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ के एक डिस्ट्रिक्ट दांतेवाड़ा में कोई खेती नहीं हुई। वहां 1354 गांव हैं। उनमें से 600 गांवों में कोई खेती नहीं हुई। उस दिन मैंने नैशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का मिनिचर पढ़कर सुनाया था, आपने नहीं सुना कि जो माओइस्ट हैं, टैररिस्ट्स हैं या मिलिटेंट्स हैं, वे काम करते हैं। मैं निखिल कुमार सिंह जी की बात के ऊपर बोल रहा था कि पहला काम वे यह करते हैं कि गवर्नेंस नहीं हो। सरकारी एजेंसी कोई काम नहीं करे। प्रधान मंत्री बोल रहे हैं, सिक्योरिटी एडवाइजर बोल रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बोल रही है कि डैवलपमेंट को भी साथ-साथ ले जाना पड़ेगा। आप भी बोले कि दोनों तरफ एप्रोच होनी चाहिए, लेकिन वे तो पहली जिम्मेदारी यह लेंगे कि कोई डैवलपमेंट का काम नहीं हो। लैक ऑफ डैवलपमेंट को वे एक्सप्लाइट करेंगे। सड़क बन जाए, गांव में लोग चले जाएं, वे ऐसा नहीं करने देंगे। जहां बताया कि 42 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में खेती नहीं हो रही है, वहां क्या गरीबी उन्मूलन हो रहा है, वहां तो गरीबी और बढ़ रही है। इस प्रकार यह एक डायकौटोमी है। उनकी रणनीति यह है कि वे आपकी डैवलपमेंट स्कीम को गांवों में नहीं पहुंचने देंगे। फिर करप्शन आदि बाकी सब झमेले तो हैं ही, लेकिन जो कुछ भी मिनीमम है, वह एबसैंस होगा। दूसरी तरफ हम कहेंगे कि जब तक आप डैवलपमेंट नहीं करेंगे, तब तक लोगों का कल्याण नहीं होगा। इसलिए आपको अपने स्ट्रैटैजिक एक्शन को भी बदलना पड़ेगा।

सभापति महोदय : अब आप कन्क्लूड कीजिए।

मोहम्मद सलीम : साहब, आप दूसरे, तीसरे विषय लीजिए, लेकिन आप इस विषय के साथ आंख मिचौली नहीं कर सकते हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आज इस डिबेट को कन्क्लूड मत कीजिए।

सभापति महोदय : मैं इस डिबेट को कन्क्लूड करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि माननीय सदस्य से अपना भाषण कन्क्लूड करने के लिए कह रहा हूं। डिबेट तो चलती रहेगी।

मोहम्मद सलीम : महोदय, मैं आपसे यह विनती करता हूं कि आप अगर बोलो, नन्दीग्राम, तो नन्दीग्राम भी, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी रही कि इस साल के 11 महीने हमें मजबूर किया गया कि इस बारे में थोड़ी और इनडैप्थ स्टडी की जाए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे अपने मित्रों के साथ और पूरे देश के साथ शेयर करूं। इसमें यदि आपको कहीं ऐसा लगे कि मैं परदा डाल रहा हूं, तो बेशक आपको बोलने का हक है, लेकिन हमें कहीं न कहीं इस विषय के ऊपर तवज्जुह देनी पड़ेगी। इसलिए मैं सरकार की तवज्जुह मांग रहा हूं। खैर, मैंने चार विषय बताए हैं। मैं चारों विषयों पर बोलूंगा। एक जो नॉर्थ ईस्ट में जम्मू-कश्मीर का जो मिलिटेंसी अफैक्टेड एरिया है, दो माओइस्ट, जो लैफ्ट एक्स्टीमिज्म की बात आप कर रहे हैं, तीन जो आतंकवाद का हमला है और चार जिस तरह से रिलीजियस बायगौट्री, फंडामैंटलिज्म इरैस्पैक्टिव, मैं धर्मनिरपेक्ष होकर बोल रहा हूं। उसे एक्सप्लौइट कर के यंगर जनरेशन को जिस तरह से बहाया जा रहा है, ये चारों हमारे देश के लिए खतरा बन रहे हैं, फिर चाहे आज हो या कल हो, इस जिले में हो या उस जिले में। मैं अभी सिर्फ माओवादी को ही डील कर रहा था। अगर आप इजाजत देंगे, तो मैं बाकी और तीनों विषयों पर भी बोलूंगा। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आंकड़े पूरे हैं। [r46] लेकिन जहां से मैंने शुरू किया था कि डैवलपमेंट आपको ले जाना

पड़ेगा और वह मैसिव सिस्टम नहीं, सुपर कॉप, अच्छे यंत्र, अच्छी गाड़ी की बेशक सब को जरूरत है, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसा बोलते हैं कि हमारे लिए आप 40 हजार करोड़ रुपये से 50 हजार करोड़ रुपये इस देश में, इस गरीब मुल्क में सालाना सैण्ट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और वैरियस एजेंसीज़ इण्टरनल सिक्योरिटी पर हम खर्च करते हैं और जिस तरह से चुनौती बढ़ रही है, खर्च और भी बढ़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि ये 40-50 हजार करोड़ रुपये, जो हम खर्च कर रहे हैं, how much intelligently, strategically, target-oriented, performance-driven किस तरह से हम अपने गोल को निर्धारित करके उसको एचीव कर सकते हैं, यह देखना संसद का काम है। संसद आपसे यह गुजारिश करेगी कि आप 50 हजार करोड़ रुपये की जरूरत हो, 60 हजार करोड़ रुपये खर्च करें, but it should be result-oriented. लेकिन हम सामान खरीद रहे हैं, हम जरूरत पड़े तो भेज रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चूंकि हमारे पास आंकड़ा है, इसलिए मैं सरकार से यह कहूंगा, हमारे मंत्री जी ने पिछली चर्चा में यह कहा था, जब आडवाणी जी ने यह चर्चा उठाई थी कि पूरे देश में नक्सलाइट इफैक्टिड एरियाज़ में घटनाएं कम रही हैं, मौतें कम रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की वजह से आंकड़ा बढ़ गया। मैं छत्तीसगढ़ को इन आइसोलेशन नहीं देखना चाहता। छत्तीसगढ़ हाथ से दूर जायेगा तो आध्र प्रदेश हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, आज नहीं तो कल हम इफैक्टिड होंगे। बंगला में एक कहावत है, गोबर से जलाने के लिए गोंटा बनाते हैं तो गोबर हंसता है कि देखो, लेकिन गोबर को भी यह समझना चाहिए कि अगर गोंटा जल रहा है तो कल को उसकी हालत भी यही होगी। मैं शाहनवाज़ जी को भी यही कह रहा था कि आप ऐसा मत करो।...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैं सलीम साहब से यही कह रहा हूं कि थोड़ा आतंकवादियों के खिलाफ भी बोलें।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please take your seat.

...(*Interruptions*)

सभापति महोदय : आप स्थान ग्रहण करिये, माननीय सदस्य यील्ड नहीं कर रहे हैं।

â€¦(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I am not allowing. Shri Shahnawaz Hussain, please take your seat.

*(Interruptions) â€¦**

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please address the Chair. आप यील्ड नहीं कर रहे हैं तो आप खड़े कैसे हो गये? मि. सलीम, आप यील्ड कर रहे हैं?

...(*Interruptions*)

मोहम्मद सलीम : मैं बोलता हूं कि इसको कम्युनल सोच बोलते हैं। व्यक्तिगत रूप से अगर मजाक भी किया तो ये पूरी माइनोरिटी के प्रतिनिधि बन गये। किस माइनोरिटी ने तुम्हें प्रतिनिधि बनाया, भइया? ...(व्यवधान)

---

* Not recorded

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : ये मल्होत्रा जी को देखकर कह रहे हैं, मैं इनका इशारा नहीं समझता हूं क्या? इन्होंने क्या इशारा किया है, मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझ रहा हूं।...(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : देखिये, वे बी.जे.पी. में माइनोरिटी बन गये और मल्होत्रा जी को कह रहे हैं कि वे मैजोरिटी बन जायें।...(व्यवधान) हम कभी-कभी दूसरों के ऊपर हंसते हैं...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सलीम जी, आप कन्क्लूड कीजिए। अब चार बज रहे हैं, इसलिए मैं दूसरा विषय लूंगा। मुझे अब दूसरा विषय लेना पड़ेगा, इसलिए आप कन्क्लूड कीजिए।

मोहम्मद सलीम : मैं यह कह रहा था कि जो जियो पोलिटिकल...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपके पास दो मिनट का समय है, आप कन्क्लूड कीजिए। मुझे चार बजे दूसरा विषय लेना होगा, चूंकि ऐसा तय कर चुके हैं।

मोहम्मद सलीम : इस देश की जो हमारी सामाजिक और भोगौलिक स्थिति हो रही है, उसको हम अगर समझ में नहीं लाएंगे तो जो भी हम खर्च करें, जो भी हम काम करें, वह फुलफिल नहीं होगा। मेरे बोलने का मकसद यही है और इस जगह पर खड़े होकर अगर आप देखें कि गौहाटी में जो हुआ, असम में जो हुआ, एक तो यह जो ट्राइबल एरिया है, जो डिस्कंटेंटमेंट है, जो कमोशन है, लैक ऑफ डैवलपमेंट है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ ट्राइबल्स की मांग है, उसके इस्तेमाल को लेकर चाहे उसको बहकायें, चाहे उसको बरगलायें, लेकिन उसका जब इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद जब रिटेलिएशन हुआ तो यह जब टेलीविजन में देखते हैं कि ट्राइबल गर्ल को जिस तरह से विवशता के साथ व्यवहार किया जाता है, वे आपके जो सेंटीमेंट्स हैं, उसको राउज़ कर देते हैं और पोलिटिकली जो हम एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ है, हम सरकार के खिलाफ हैं, जो एक्सट्रीमिज्म है, जो मिलीटेंसी है, वे उसको एंटी स्टेट कर देते हैं।[R47]

16.00 hrs.

जो एंटी गवर्नमेंट है, जो एंटी स्टैब्लिशमेंट है, उसको पूरा स्टेट, ऐज एन स्टैब्लिशमेंट, उसकी जगह पर उसे ले जा रहे हैं। हम लोगों को यह देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि ऐसा माहौल नहीं बने, जहां एक पार्टी के खिलाफ दूसरी पार्टी का जो रवैया है, उसे एक मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करें, चाहे वह फंडामेंटलिस्ट हों, चाहे मिलिटेंसी हों, चाहे एक्सट्रीमिज्म हों या चाहे टेररिज्म हों। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप जल्दी समाप्त कीजिए। चार बजे बिल लेना है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : आप उन्हें बोलने दीजिए।

सभापति महोदय : आप जल्दी समाप्त करिए।

मोहम्मद सलीम : महोदय, जल्दी समाप्त करने का सवाल ही नहीं है। वह तभी उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ बड़ा इंपार्टेंट है फाइनेंसेज का सवाल, आपने खुद मनीलेंडरिंग में यह सब किया। अभी मल्होत्रा जी ने एक रिपोर्ट पढ़ी। हिंदुस्तान टाइम्स में यूएन की रिपोर्ट लिखी है, उसमें कई विषय है। मल्होत्रा जी ने कानून की बात कही। उसमें हमारा और उनका अंतर हो सकता है। मैं उस बारे में बाद में आऊंगा, लेकिन उसके साथ यह भी है कि जो फंड मूव करता है, इस तरह की सुरक्षा का अभाव पैदा करने के लिए, आतंकवादी हमला करने के लिए और उसके लिए जो ट्रैप करना चाहिए, उसके लिए जो इंटेलीजेंस करनी चाहिए, उसके लिए हमारे यहां फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट है, वह काम कर रही है। अभी मैं देख रहा था कि मध्य प्रदेश में बिजनेस ओके है, इंटरनल हवाला, एक देश से दूसरे देश को पैसा भेजने को हवाला बोलते हैं, इंटरनल हवाला, जैसे दिल्ली से भोपाल में, भोपाल से कलकत्ता में, कलकत्ता से रांची में, इस तरह अगर पैसे का लेन-देन करना पड़े, तो बैंक में ड्राफ्ट वगैरह नहीं करके, वे एक सेविंग डील करते हैं, इसमें जेन्यूइन पैसा भी हो सकता है, ब्लैक ही नहीं व्हाइट भी हो सकता है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आप डिस्टर्ब न करें।

मोहम्मद सलीम : यह जो ट्रंजेक्शन होता है, अगर यह शैडो में हो रहा है, तो फिर आपको फाइनेंशिल बैंक जो ट्रैप करेंगे, जैसा हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा था कि बैंक एकाउंट से कितना-कितना रूपया जा रहा है, वह तो नहीं आएगा और हम सब का अनुभव है कि ऐसा ट्रंजेक्शन होता है और जब तक हम उस रूट को नहीं पकड़ पाएंगे, यूएन रिपोर्ट भी कह रही है कि आपका फाइनैंशियल ट्रंजेक्शन है, उसे ट्रैप करना चाहिए, वहां फंडिंग कैसे हो रही है, इसका पता लगाना चाहिए। इसी तरह से उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आपके यहां जो एक्सपर्टीज इंटेलीजेंस गैदरिंग करने की कई किताब लिखी हैं, अभी दो-तीन किताब तो आयी हैं, रॉ के बारे में, हमारे इंटेलीजेंस के बारे में, कि हमारी खुफिया एजेंसियों के अंदर क्या काम है? हमारे देश में विघटन हो रहे हैं, उसके लिए विदेशी तत्वों को और उसकी इंटेलीजेंस एजेंसी को बेशक गाली दें, उनका कुछ हाथ भी है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कंक्ल्यूड कीजिए।

मोहम्मद सलीम : कंक्ल्यूड करने का सवाल ही नहीं है, मैंने तो अभी शुरू किया है। ठीक है अगर आज कुछ और करना है,तो मैं कल बोलूंगा। मुझे बीस मिनट और बोलने के लिए चाहिए।

सभापति महोदय : आप कंक्ल्यूड कीजिए।

श्री अनिल बसु : महोदय, आप उन्हें बोलने दीजिए।

मोहम्मद सलीम : अगर डिस्कशन कल तक चलेगा, तो मैं कल बोलूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

सभापति महोदय : आप 27 मिनट बोल चुके हैं। आप कंक्ल्यूड कीजिए।

मोहम्मद सलीम : हम पिछले शनिवार से इंतजार कर रहे हैं कि इस विषय पर बिना कोई बाधा चर्चा हो। यह पिछले शनिवार को रखा गया था। अगर आप चार बजे बिल लेना चाहते हैं, तो मैं कल कर लूंगा।

सभापति महोदय : आप कंक्ल्यूड करिए, उसके बाद में उसे लेंगे।

मोहम्मद सलीम : मुझे आपको दस मिनट समय और देना पड़ेगा।

सभापति महोदय : आप 27 मिनट बोल चुके हैं, आप पांच मिनट में कंक्ल्यूड करिए।

मोहम्मद सलीम : जिस तरह से ये बम विस्फोट वगैरह हो रहे हैं, अगर आप देखें कि जो टीनेजर्स हैं, जो पोस्ट 92 जेनरेशन है, मुसलमानों के अंदर, उसकी एक अलग सी सोच है। यह सोच इसलिए है, वह एक फाडर है, उसे कौन इस्तेमाल करेगा, इसके लिए फंडामेंटलिस्ट आर्गेनाइजेंशंस, जो रिलीजियस आर्गेनाइजेंशस हैं, वे भी यह समझते हैं कि माडरेट ब्वायज काम नहीं कर रहे हैं, जितने मुस्लिम तंजीम हैं, उनके बड़े-बड़े प्रतिष्ठित नेता हैं, वह नौजवान उनकी बात को भी नहीं सुन रहा है, क्योंकि इस देश में अस्सी और नब्बे के दशक में देखा गया कि हिंदू कम्युनलिज्म को माडरेट से आगे बढ़ाकर अगर आप शेर के पीछे चढ़ जाते हैं, तो आप क्षमता में चले जाते हैं। [p48] उसका एक काउंटर रिस्पौंस होता है कि हमें भी मॉडरेट से हार्डलाइनर में ट्रंज़िट करना है और वह पूरे देश में हो रहा है। हमारे लिए वह बहुत बड़ा खतरा है। सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के बाहर की ताकत भी उसे टारगेट करेंगे। अगर आप देखें तो पूरे विश्व में, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड, हमारे बाजू में पाकिस्तान, बंगलादेश तो है ही, पूरे विश्व में पोस्ट 9/11 श्री बुश ने ऐसी स्थिति बनाई है कि एक अजीब सी जियो पोलीटिकल स्थिति बनी है कि पोलीटिको रिलीजियो अपसर्ज हो रहा है। हमारे देश में क्या हो रहा है? आज 5 दिसम्बर है। 1992 के बम विस्फोट के बाद अभी भी लिब्राहन कमीशन को एक्सटैंशन दी जा रही है, लेकिन आज तक राय नहीं बनी। विश्व में भारतवर्ष एकमात् ऐसा देश है जहां गिनती उलटी हो रही है। हमने ज़ीरो का अविष्कार किया है। 1992 पहले आता है, उसके बाद 1993 आता है। मुम्बई बम विस्फोट हुए, बेशक हर दोषी को सजा मिलनी चाहिए और 16 साल बाद सजा मिल रही है, लेकिन 1993 वालों को सजा मिल रही है और जो लोग 1992 के कसूरवार हैं, वे सिर उठाकर घूम रहे हैं। यह लोगों के अंदर एक अजीब व्यवस्था पैदा करती है। इससे एक साप्रदायिक स्थिति बन रही है। अल्पसंख्यकों में जो साप्रदायिक राजनीति करना चाहते हैं, अल्पसंख्यक के अंदर जो फंडामेंटलिस्ट्स हैं, उस फोर्स को बल मिल रहा है। उसकी लिबरल वॉयस स्कवीज हो रही है और हम अपने लोकल पोलीटिकल गेन के लिए कभी-कभी उसको सहारा देते हैं कि कभी उसका भरोसा कर लो, कभी उसका

भरोसा कर लो। वह कम्युनल लीडरशिप के हाथ में नहीं रहेगा, वह एक्सट्रीमिस्ट्स के हाथ में जाएगा, वह और किसी खतरनाक हाथ में जाएगा। लेकिन हम दूसरी तरफ क्या करते हैं? एक बम विस्फोट होता है। इसमें कुछ स्टैन्डर्ड मीन्स हैं। हम बोल देते हैं यह संस्था, वह संस्था, कुछ टैररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उसको सही तरीके से इन्वैस्टीगेट करके, उसके कसूरवार को ढूंढकर उसके बाद उसे सजा दो। जो एक्सट्रीमिस्ट आर्गनाइजेशन्स होते हैं, कोई भी हो, चाहे वह लैफ्ट एक्सट्रीमिस्ट हो, रिलीजियस बॉयगॉटरी हो, चाहे मिलिटैंट आर्गनाइजेशन हो, जब कोई घटना घटवाता है तो वह सस्ती पब्लिसिटी लेना चाहता है। वह लीफलेट छापकर बांटता है कि देखो, हम यह कर रहे हैं। वह अखबार वालों को फोन करता है , टेलीविजन चैनल को बेनामी फोन करता है, ई-मेल करता है, क्योंकि वह आम साधारण नागरिक को दहशत में डालकर, दहशतगर्द का मतलब ही होता है कि दहशत पैदा करके सस्ती पब्लिसिटी लेकर, चाहे उसकी गलत आइडियोलोजी हो, चाहे गलत प्रचार हो, लेकिन वह उस दुष्प्रचार को सामने लाने की कोशिश करता है। हमारे यहां जितने भी विस्फोट हो रहे हैं, आजकल कोई संस्था क्लेम नहीं करती। जब वे खर्च करके, ट्रेनिंग देकर यह काम कर रहे हैं तो उन्हें क्लेम करना चाहिए। यह एक नई टैन्डैन्सी है, नया ट्रैंड है। इसलिए मैंने कहा कि आपको इन्फार्मेशन गैदरिंग सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रैन्दन करना पड़ेगा और सरकार, पुलिस, मीडिया,...(व्यवधान) हकीकत की तह में जाना चाहिए। हमें जरूरत है। हो सकता है कि उनकी टैक्टिक्स ऐसी है कि अलग-अलग जगह पर अलग-अलग जरिए से वे यह सब करवा रहे हैं, आजकल सुपारी होती है। लेकिन हम उसकी तह में नहीं जाते। मैं सरकार से मांग करूंगा, पिछले साढ़े तीन सालों में जितने विस्फोट हुए, आप आंकड़े देखकर बताएं कि आपने कितने लोगों को इनीशियली अरैस्ट किया, कितने लोगों के ऊपर आपने मुकदमे दायर किए, कितने लोगों को चार्जशीट दी, कितने लोगों को रिलीज़ कर दिया और कौन संस्था, कौन व्यक्ति, कौन ग्रुप, कौन गिरोह इसके पीछे है।...(व्यवधान) यह भी एक बड़ा मसला है।

इसके साथ-साथ आखिर में वर्ड ऑफ कॉशन कहना चाहता हूं। जिस तरह पाकिस्तान के मामले चल रहे हैं, जिस तरह से अफगानिस्तान के मामले चल रहे हैं, हो सकता है जम्मू कश्मीर में अभी थोड़ा लल है, लेकिन सरकार के एडवाइज़र, सिक्युरिटी सलाहकार ने खुद कहा है कि मिलिटैंसी का जो इनफिल्ट्रेशन हुआ है, वे कुछ लोकल रिक्रूट करेंगे, जैसे मैंने कहा कि जब ऐसे हालात बनते हैं तब उसमें लोकल रिक्रूट करते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जिस तरह नार्थ फ्रंटियर चल रहा है, उससे हमारी तसल्लीबख्श स्थिति नहीं है बल्कि इसका असर कश्मीर के ऊपर फिर से आ सकता है। उसके लिए भी सरकार को सावधान करना पड़ेगा। इसी तरीके से बंगलादेश का मामला भी है। अगर आप देखेंगे कि बंगलादेश में डेमोक्रेसी न होने के कारण दो इस्टैबलिश्ड पोलीटिकल पार्टीज, मैं उनकी इंटरनल पोलीटिक्स पर नहीं बोलूंगा, लेकिन करप्शन आदि के मामले जो भी हों, जिस तरह उनके ऊपर अंकुश लगाया जा रहा है, लेकिन बीच में फंडामैंटलिस्ट फोर्स निरंकुश हो रही है। जो डेमोक्रेटिक फोर्स है, जो पोलीटिकल सिस्टम है, जब पोलीटिकल पार्टीज काम नहीं करतीं, जब पोलीटिकल सिस्टम काम नहीं करता है तो उस जगह ऐसे एक्सट्रीम फोर्सेज को पनपने का मौका मिल जाता है।[N49] उसका असर हमारे नार्थ ईस्ट में, बंगाल में, पड़ता है। इसके अलावा जहां नार्थ बिहार बंगाल का बॉर्डर है जिसे चिकन नैक कहा जाता है, जहां से हमारे पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जीतकर आये हैं, उस पर खतरा हो सकता है। नेपाल और भूटान की सीमा है, जो सॉफ्ट बॉर्डर है जिसे हम ज्यादा गार्ड नहीं करते हैं, कोई भी थर्ड कंट्रीज, हमारे देश की अंदरूनी ताकतें उसे भी ट्रांजिट के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं और उन्हीं के द्वारा यह व्यवहार हो रहा है। हमारे यहां फिर रेड कारीडोर, जिसकी आप बात करते हैं, जो माओइस्ट मामला है, उसके लिए हमें तय करना पड़ेगा कि क्या हम इसको पोलिटिकल सहारा देंगे, हम उसको छोटे-मोटे फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे कि चलो वह उस पार्टी के खिलाफ है, इस पार्टी के खिलाफ है, क्या हम उस तरीके से हम जायेंगे या हमको एक पोलिटिकल तरीका अपनाना पड़ेगा कि नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से हमारा जो विरोध है, उसे हम प्रकट भी कर सकते हैं, लड़ भी सकते हैं लेकिन सस्ते फायदे के लिए हम एक लम्बे ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Mr. Chowdhury, I am not allowing you. Please sit down. Nothing will go in the record except the speech of Md. Salim.

*(Interruptions) â€¦ **

मोहम्मद सलीम : मैं अंत में सिर्फ एक बात कहूंगा कि आंतरिक सुरक्षा में जो खतरा है, वह माओइस्ट, लैफ्ट एक्सट्रीमिज्म, नार्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी है, जो हमारी फंडामेंटलिस्ट फोर्स है वह चाहे किसी भी रिलिजन का सहारा लेती हो और जो आर्गनाइज्ड क्राइम इंडीकेट्स हैं। माओइस्ट एक, फंडामेंटलिस्ट दो और मिलिटेंसी तीन ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing would go on record.

(Interruptions) â€¦

मोहम्मद सलीम : यह सिर्फ आर्गनाइज्ड क्राइम इंडीकेट्स हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ...(व्यवधान)

* Not recorded

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : सभापति महोदय, यह नियम 193 कल किस समय लिया जायेगा। संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं, वे इस बारे में बतायें।

सभापति महोदय : यह तो आपको लिस्ट ऑफ बिजनेस से पता चल जायेगा। ...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): मैंने इस सदन में आग्रह किया था कि यह बहस कल भी चलेगी। क्वेश्चन ऑवर के बाद स्पीकर साहब टाइम तय कर देंगे। उस हिसाब से यह डिसकशन चलेगी। मैं आपको अभी टाइम नहीं बता सकता। स्पीकर साहब ने खुद कहा कि इस चर्चा को कल भी चलायेंगे। अब टाइम स्पीकर साहब तय करेंगे। शाम को जब बिजनेस तैयार होगा, तब छपकर आयेगा। लेकिन आप कल ऐसा माहौल बनाइये कि हाउस चले।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): यही लोग हल्ला करेंगे। आज इन्होंने बोल दिया है इसलिए कल यह हल्ला करेंगे। जब हम लोगों के बोलने की बारी आयेगी, तो यह हल्ला करेंगे। ये कल हल्ला नहीं करेंगे, इसका क्या एश्योरेंस है? ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब इस पर कल पुनः चर्चा होगी। इस पर शाम को समय निर्धारित किया जायेगा। आप लोग लिस्ट ऑफ बिजनेस में देख लीजिए। अभी हम आइटम नम्बर 24 ले रहे हैं। इसमें तीन विधेयक हैं। सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे पांच-पांच मिनट बोलने का समय लें तभी विधेयक पारित करने का काम सम्पन्न हो सकता है। अभी हम इंदिरा गांधी नैशनल ट्राइबल यूनीवर्सिटीज बिल, 2007 ले रहे हैं।

16.14 hrs.

.

-